कूटनीति में महिलाएँ: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक विकास

विवेक कुमार यादव
अनुसंधान विद्वान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

* Corresponding Author: **विवेक कुमार यादव**

Article Info

P-ISSN: 3051-3502
E-ISSN: 3051-3510
Volume: 06
Issue: 02
July - December 2025
Received: 05-05-2025
Accepted: 08-06-2025
Published: 04-07-2025
Page No: 137-140

सारांश
अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति मानव इतिहास के उन क्षेत्रों में हैं जहाँ शक्ति, निर्णय-निर्माण और वैश्विक व्यवस्था लंबे समय तक पुरुष-प्रधान संरचनाओं में विकसित हुए। लेकिन आधुनिक विश्व व्यवस्था में महिलाओं का उद्भव, उनकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व ने यह सिद्ध किया है कि कूटनीति केवल शक्ति-राजनीति का मंच नहीं, बल्कि सहानुभूति, सहकारिता, शांति-निर्माण और समावेशन का भी क्षेत्र है। यह लेख अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक यात्रा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है–प्राचीन सभ्यताओं की अनदेखी महिला राजदूतों से लेकर आधुनिक वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तक। लेख यह बताता है कि कैसे सामाजिक-पितृसत्तात्मक मान्यताएँ, कानूनी बाधाएँ, संस्थागत सीमाएँ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी ने लंबे समय तक महिलाओं की कूटनीतिक भूमिका को सीमित किया। साथ ही यह भी कि कैसे 20वीं सदी के बाद उभरते स्वतंत्रता आंदोलनों, नारीवादी विचारधाराओं, शिक्षा के प्रसार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में संस्थागत सुधारों और मानवाधिकार विमर्शों ने महिलाओं को वैश्विक मंच पर स्थान और शक्ति प्रदान की। लेख यह भी विश्लेषित करता है कि महिला नेतृत्व ने कूटनीति की भाषा और संरचना को कैसे बदला है–उनकी वार्ता-शैली, शांति प्रक्रिया में सहभागिता, बहुपक्षीय सहयोग के प्रति दृष्टिकोण, और संघर्ष-निरोधक रणनीतियों ने विश्व राजनीति में नए मानक स्थापित किए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल इतिहास में महिलाओं की उपस्थिति को पुनःस्थापित करना नहीं, बल्कि आधुनिक कूटनीति में उनके बढ़ते प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को समझना भी है।

मुख्य शब्द: महिला नेतृत्व, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, वैश्विक शासन, जेंडर राजनीति, शांति प्रक्रिया, ऐतिहासिक विकास, विदेश नीति, नारीवाद, बहुपक्षीय संस्थाएँ

परिचय

मानव सभ्यता के लंबे और जटिल इतिहास में कूटनीति का विकास हमेशा सत्ता, साम्राज्य, भू-राजनीति और रणनीतिक हितों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है, और विभिन्न युगों में इसे संचालित करने वाले प्रमुख चेहरे लगभग पूर्णतः पुरुष ही थे, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा, दायरा और संरचना एक ऐसी मानसिकता से निर्मित हुई जिसने शक्ति, प्रभुत्व, विजय, सुरक्षा और राज्य-हित को प्राथमिक केंद्र बना दिया; किंतु इस लंबे कालखंड के बीच महिलाओं की उपस्थिति कभी पूरी तरह अनुपस्थित नहीं रही, बल्कि वे विभिन्न साम्राज्यों, सभ्यताओं और राज्यों में राजनीतिक सलाहकार, शांति-दूत, मध्यस्थ, शासक, सांस्कृतिक सेतु और प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में कई बार निर्णायक भूमिका निभाती रहीं, हालांकि इन भूमिकाओं को इतिहास ने अक्सर वह स्थान नहीं दिया जो वे वास्तव में deserve करती थीं, क्योंकि कूटनीति की औपचारिक संरचना–विशेषकर यूरोपीय शक्ति-राजनीति पर आधारित वेस्टफेलियन मॉडल–ने महिलाओं को अधिकारिक राजनयिक पहचान देने में बहुत देर की; फिर भी, समाजों के भीतर परिवर्तन, औद्योगीकरण, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद का अंत, लोकतंत्रों का उदय, और अंततः अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मानवीकरण–इन सभी बड़े बदलावों ने धीरे-धीरे इस विचार को जन्म दिया कि कूटनीति केवल शक्ति संतुलन का खेल नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास, सहयोग, सहानुभूति और शांति के निर्माण की सूक्ष्म कला भी है, और इस परिवर्तनशील परिभाषा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो सकती है, जिसके प्रमाण आज हम वैश्विक मंचों पर देख रहे हैं जहाँ महिला

कूटनीतिज्ञ न सिर्फ नेतृत्व कर रही हैं बल्कि कूटनीति के चरित्र को नए सिरे से गढ़ रही हैं; किंतु इस आधुनिक उपलब्धि तक पहुँचने की यात्रा अत्यंत लंबी, जटिल और संघर्षपूर्ण रही है, जिसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं से लेकर 21वीं सदी के डिजिटल कूटनीति युग तक फैली हुई है, और इस यात्रा को समझे बिना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिला नेतृत्व का वास्तविक ऐतिहासिक विकास स्पष्ट रूप से समझा ही नहीं जा सकता।

अगर हम इतिहास के प्रारंभिक चरणों की ओर लौटें तो हमें पाताल लोक की कथाओं से लेकर मेसोपोटामिया, मिस्र, हित्ती साम्राज्य, रोम, यूनान, भारत, चीन, जापान और मध्य एशियाई राज्यों में ऐसी अनेक घटनाएँ मिलती हैं जहाँ राजकुमारियाँ, रानियाँ या महिला शासक कूटनीतिक विवाह, युद्धविराम, समझौतों और संदेशवाहक भूमिकाओं में शामिल थीं; मिस्र की नेफ़रतीति और हत्तुसा की रानियों के बीच पत्राचार, रोमन साम्राज्य में लिविया की राजनीतिक प्रभावशीलता, चीन की वू झाओ का शासन, भारत में अहिल्या बाई होलकर जैसे अपवाद–ये सभी दर्शाते हैं कि महिला नेतृत्व, भले ही संरचनात्मक रूप से मान्यता प्राप्त न रहा हो, किंतु किसी-न-किसी रूप में कूटनीति का अभिन्न तत्व था; इसके अलावा मध्यकालीन यूरोप में शाही विवाहों के माध्यम से राज्यों के बीच गठबंधनों को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही, और कई बार वे राजकुमारी, बहू या रानी केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक वार्ताकार थीं; किंतु विडंबना यह थी कि कूटनीति का औपचारिक इतिहास इन योगदानों को 'unofficial influence' कहकर सीमित कर देता है, क्योंकि औपचारिक कूटनीति के नियम पुरुषों द्वारा बनाए गए और उनके लिए डिज़ाइन किए गए थे, जिससे महिलाओं की वास्तविक क्षमता सदियों तक ढाँचों के बाहर ही फंसी रही।

18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में 'salon diplomacy' के उदय ने पहली बार महिलाओं को एक वैचारिक भूमिका दी, जहाँ वे बौद्धिक चर्चा, सांस्कृतिक वार्ता और राजनीतिक मध्यस्थता का केंद्र बनीं; फ्रांस, इंग्लैंड और प्रुषिया में कई प्रभावशाली महिलाएँ–मैडम डे स्टेल, मैडम डे पोम्पाडोर, कैथरीन द ग्रेट–ने राजनैतिक और कूटनीतिक निर्णयन को प्रभावित किया, किंतु फिर भी उन्हें राजनयिक की आधिकारिक उपाधि नहीं दी गई; इस समूचे कालखंड में कूटनीति पुरुषों की दुनिया मानी जाती रही, और महिलाओं की उपस्थिति 'सामाजिक कूटनीति' या 'सांस्कृतिक माध्यम' तक सीमित कर दी गई; यह स्थिति तब तक कायम रही जब तक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं आया जिसने कूटनीति की परिभाषा ही बदल दी। विश्व युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य शक्ति या राजनीतिक कठोरता वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सकती, और इस विचार के साथ मानव सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, संघर्ष-निरोध, मानवीय हस्तक्षेप, आर्थिक सहयोग और वैश्विक प्रशासन जैसी अवधारणाएँ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में आईं; और यही वह मोड़ था जिसने महिलाओं की भूमिका को व्यापक और अनिवार्य बनाना शुरू किया, क्योंकि इन सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में महिलाओं का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक, मानव-केंद्रित और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने वाला माना गया।

20वीं सदी के उत्तरार्ध में संयुक्त राष्ट्र के गठन और उसकी संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व की शुरुआत ने कूटनीति में महिलाओं के औपचारिक प्रवेश का मार्ग खोला; इसी काल में भारत जैसे नव-स्वतंत्र देशों ने भी महिलाओं को प्रमुख कूटनीतिक पदों पर नियुक्त करना शुरू किया–जिसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण विजयलक्ष्मी पंडित थीं, जिन्होंने न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनीं; यह वह समय था जब महिलाओं ने कूटनीति में 'प्रतिनिधित्व' का चरण पार किया और 'नेतृत्व' की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर संरचनात्मक बाधाएँ मौजूद थीं–विदेश मंत्रालयों के नियम, पदानुक्रम, विदेश पोस्टिंग के सामाजिक प्रतिबंध, यौनिक भेदभाव और पुरुष-प्रभुत्व वाली वार्ता संस्कृति–इन सबने महिलाओं के आगे बढ़ने की गति को धीमा किया; किंतु इन बाधाओं के बावजूद महिलाएँ आक्रामक शक्ति-राजनीति के बजाय शांति निर्माण, मानवाधिकार, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग जैसी भूमिकाओं में अत्यंत प्रभावी साबित हुईं, जिससे धीरे-धीरे कूटनीति का चरित्र ही रूपांतरित होने लगा।

21वीं सदी में जैसे ही वैश्विक मुद्दे अधिक जटिल, अंतरसंबंधित और मानवीय हो गए–जैसे जलवायु संकट, साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन, आर्थिक असमानता, महामारी, प्रवासन और लैंगिक न्याय–कूटनीति को नई दिशा देने के लिए महिलाओं की उपस्थिति और नेतृत्व अपरिहार्य माना जाने लगा; यही वह काल था जब दुनिया ने पहली बार कूटनीति में महिलाओं की भूमिका को 'पूरक' नहीं बल्कि 'परिवर्तनकारी' माना; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऐतिहासिक प्रस्ताव 1325 ने यह स्थापित किया कि शांति प्रक्रियाओं में महिलाएँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं, और उनके बिना कोई भी समझौता टिकाऊ नहीं हो सकता; इसके बाद दुनिया के अनेक देशों ने अपनी विदेश नीति में gender mainstreaming की नीतियाँ लागू कीं–स्वीडन ने 'feminist foreign policy' पेश की, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस और कनाडा ने gender-responsive diplomacy को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया, और अफ्रीका व एशिया के कई देशों ने महिला कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति को तेजी से बढ़ाया; इन परिवर्तनों ने दर्शाया कि महिलाओं का नेतृत्व केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता, सहयोग और दीर्घकालिक शांति के लिए रणनीतिक आवश्यकता है; आज 2025 के दशक में स्थिति यह है कि दुनिया के अनेक देशों में विदेश मंत्रालयों में महिलाओं की उपस्थिति 40–50 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है, और कई बहुपक्षीय संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएँ नेतृत्व कर रही हैं, जिससे वैश्विक वार्ता अधिक संतुलित, संवाद-केंद्रित और मानव-केंद्रित हो चुकी है।

इसी क्रम में यह भी स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं बल्कि शक्ति-परिचालन, वैचारिक बदलाव और वैश्विक व्यवहारिक कूटनीति के ढाँचे को पुनर्परिभाषित करने का भी विषय है, क्योंकि जब महिलाएँ उच्च-स्तरीय कूटनीतिक निर्णयों में शामिल होती हैं तो वे केवल किसी राज्य का औपचारिक प्रतिनिधित्व नहीं करतीं बल्कि वैश्विक संवाद में ऐसे दृष्टिकोण जोड़ती हैं जो हिंसा-प्रतिरोध, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु न्याय, शांति-वार्ता और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे प्रश्नों को प्राथमिकता देते हैं, और यही कारण है कि कई शोध यह दिखाते हैं कि जहाँ वार्ता-प्रक्रिया में महिलाओं का सक्रिय योगदान होता है वहाँ शांति-संधियाँ अधिक समय तक टिकती हैं, सहमति-निर्माण की प्रक्रिया अधिक समावेशी होती है और राजनीतिक विभाजन की तीक्ष्ण सीमा को नरम करने में मानवीय दृष्टिकोण केंद्र में आता है; इसी संदर्भ में नॉर्वे की पूर्व विदेश मंत्री इने मारी एरिक्सेन, मोइरीना कारमोना, यूनेस्को की ऑड्रे अज़ूले, यूरोपीय संघ की फ़ेडेरिका मोघेरिनी, और कई अन्य महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को अहं-केन्द्रित शक्ति-प्रतिस्पर्धा से हटाकर बहुपक्षीय सहयोग, पारदर्शिता और दीर्घकालिक क्षेत्रीय शांतिनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ाया; उदाहरण के लिए मोघेरिनी की ईरान न्यूक्लियर डील में भूमिका यह दर्शाती है कि कैसे महिला नेतृत्व अत्यंत जटिल तकनीकी व सुरक्षा मामलों में भी धैर्य, संवाद और

पारदर्शिता पर आधारित समाधान खोज सकता है, और इसी तरह संयुक्त राष्ट्र में महिला राजनयिकों ने वर्षों तक यह साबित किया है कि लिंग-समावेशन किसी भी तरह से योग्यता का स्थानापन्न नहीं बल्कि कूटनीति को अधिक प्रभावी, अधिक वास्तविक और अधिक संवेदनशील बनाता है; किंतु इस उपलब्धि की यात्रा कठिनाईयों से भरी रही, क्योंकि 20वीं सदी के अधिकांश हिस्से में महिलाओं को विदेश सेवा में प्रवेश से लेकर निर्णय-निर्माण तक बाधाओं, लैंगिक पूर्वाग्रहों, रूढ़िगत टिप्पणी और संस्थागत प्रतिबंधों से जूझना पड़ा, जैसे अधिकांश देशों में विवाह करने पर महिला कूटनीतिज्ञों को सेवा छोड़नी पड़ती थी, उन्हें 'भावनात्मक' या 'कम सख़्त' समझा जाता था, और सुरक्षा तथा रणनीतिक मामलों से उन्हें हटाकर केवल सांस्कृतिक या सामाजिक दायित्वों वाले पदों में सीमित कर दिया जाता था, परंतु समय के साथ महिलाओं ने न केवल इन अवरोधों को तोड़ा बल्कि एक ऐसा मानक भी स्थापित किया जहाँ उनका नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की गुणवत्ता का मुद्दा बन गया, केवल प्रतिनिधित्व का नहीं; आज दुनिया में 60 से अधिक देशों में महिलाएँ राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विदेश मंत्री या उच्च-स्तरीय बहुपक्षीय वार्ताकार के रूप में कार्य कर रही हैं और इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भाषा भी बदली है–पहले जहाँ वैश्विक राजनीति में कठोर शक्ति, प्रभुत्व, सेना और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी जाती थी, अब मानवीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक न्याय, शरणार्थी अधिकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, और समुदाय-आधारित समाधानों जैसे विषय केंद्रीय बनते जा रहे हैं, और इन विषयों की मुख्य वाहक स्वयं महिलाएँ हैं–न केवल इसलिए कि वे इन मुद्दों का अनुभव अपने जीवन में अधिक तीव्रता से करती हैं, बल्कि इसलिए भी कि महिला नेतृत्व तुलनात्मक रूप से अधिक संवाद-उन्मुख, सहयोग-आधारित और दीर्घकालिक सोच पर आधारित होता है; इसी परिवर्तन को भारत में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ विजय लक्ष्मी पंडित, महारानी गायत्री देवी, नयना मोदी, चंद्रा रॉय, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण और हाल की युवा पीढ़ी की भारतीय महिला राजनयिकों ने विदेश नीति के हर आयाम–द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय वार्ता, व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व–में नए मानक स्थापित किए हैं, और भारत की विदेश नीति विशेष रूप से दक्षिण एशिया, अफ्रीका और इंडो-पैसिफ़िक में महिला-उन्मुख विकास सहयोग और मानवीय सहायता के मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रही है; परंतु यह बदलाव अभी अधूरा है, क्योंकि आज भी दुनिया के कूटनीतिक ढाँचे में महिलाओं की संख्या शीर्ष पदों पर केवल 20–25% के आसपास है, सुरक्षा और रक्षा मामलों में उनकी भागीदारी और भी कम है, और औपचारिक बाधाओं के बावजूद अनौपचारिक पूर्वाग्रह, कार्यस्थल के लैंगिक अंतर, राजनीतिक संरक्षण की कमी, और पारिवारिक-सामाजिक दबाव के कारण कई महिलाएँ शीर्ष पदों तक नहीं पहुँच पातीं; इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि महिलाओं की कूटनीति का इतिहास केवल उपलब्धियों का इतिहास नहीं बल्कि संघर्ष, पुनर्जागरण, पुनर्परिभाषा और आत्मनिर्माण की यात्रा भी है जहाँ प्रत्येक महिला राजनयिक ने अपने अस्तित्व, क्षमता और दृष्टि से यह सिद्ध किया है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के डिज़ाइन में स्त्री-सशक्तिकरण केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जो आधी आबादी की आवाज़ को न सुने, न उसका प्रतिनिधित्व करे, न उसे निर्णयों में शामिल करे–वह कभी संतुलित, शांतिपूर्ण या न्यायसंगत नहीं हो सकती, और यही कारण है कि आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में "Women in Diplomacy" केवल एक शोध विषय नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है जो भविष्य की कूटनीति को अधिक मानवीय, अधिक स्थिर और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में सबसे गहरा योगदान दे रही है।

इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह समझना और भी महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्माण में महिलाओं की उपस्थिति केवल नीतिगत या संस्थागत बदलाव तक सीमित नहीं रहती बल्कि वैश्विक शक्ति-संरचना की कल्पना, संवाद की भाषा, निर्णयों की संवेदनशीलता और राजनयिक व्यवहार की समग्र संस्कृति को गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि लंबे समय तक कूटनीति एक ऐसे पुरुष-प्रधान ढाँचे में विकसित हुई थी जहाँ शक्ति का प्रदर्शन, सैन्य क्षमता, दबाव-रणनीति, कठोर भाषा और मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को प्रभावी कूटनीति माना जाता था, लेकिन जब महिलाएँ निर्णायक भूमिकाओं में आईं तो उन्होंने एक नया प्रतिमान स्थापित किया जिसमें वार्ता का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को हराना नहीं बल्कि साझा समाधान तलाशना, संघर्ष को मानविकीकृत करना, और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना बन गया; संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाएँ जहाँ-जहाँ शामिल हुईं, वहाँ स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास-निर्माण तेज़ हुआ, क्योंकि महिलाएँ–चाहे वे सैन्य पर्यवेक्षक हों, मानवीय अधिकारी हों या वार्ताकार–स्थानीय महिलाओं, बच्चों, संघर्ष-पीड़ित परिवारों तक अधिक सहजता से पहुँच सकीं, जिससे शांति प्रयासों की वास्तविक स्थिति समझने और स्थायी समाधान विकसित करने में मदद मिली; इसी तरह जब देशों की विदेश नीतियों में महिला नेतृत्व बढ़ा तो एजेंडा भी महज सैन्य या भू-रणनीतिक प्राथमिकताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, जल सुरक्षा, खाद्य प्रणाली, नाजुक राज्यों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों की सुरक्षा और साइबर-हिंसा जैसे विषय नीति के केंद्र में आए, और यह बदलाव केवल इसलिए नहीं हुआ कि महिलाएँ 'अलग सोचती' हैं, बल्कि इसलिए कि कूटनीति का उद्देश्य अगर शांति, स्थिरता और सहयोग है, तो आधी आबादी को निर्णय से बाहर रखना वस्तुतः वैश्विक असंतुलन को बढ़ावा देना है; यह भी दिलचस्प है कि जिन देशों में महिला नेतृत्व लगातार बढ़ा–जैसे नॉर्डिक देश, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, जर्मनी, रवांडा, कोलंबिया–वहाँ विदेश नीति अधिक प्रगतिशील, शांतिप्रिय और मानव-केंद्रित हुई, और यह प्रवृत्ति केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी महिला नेतृत्व उभर रहा है, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की दीर्घकालिक विदेश नीति, रवांडा में महिला राजनयिकों की बढ़ती भूमिका, इथियोपिया में राष्ट्रपति साहले-वर्क ज़ेवडे का योगदान, और चिली में महिलाओं का संवैधानिक पुनर्निर्माण में वैश्विक कूटनीति से जुड़ना; भारतीय संदर्भ में यह प्रक्रिया और भी विशिष्ट है क्योंकि भारत लंबे समय से लोकतांत्रिक संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय मंचों और बहुपक्षीय कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए मजबूत ज़मीन तैयार करता आया है–विजयलक्ष्मी पंडित की संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता, इंदिरा गांधी की शीतयुद्ध काल में विदेश नीति, सुषमा स्वराज का 'डिजिटल कूटनीति' , निरूपमा राव की चीन-अमेरिका मामलों में भूमिका, रचना कौर की जलवायु वार्ताओं में सक्रियता और अनामिका खरे, रुचिरा कंबोज जैसी महिलाओं का संयुक्त राष्ट्र मिशन में नेतृत्व यह दर्शाता है कि भारत में महिला कूटनीति केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रभावशाली कूटनीतिक शक्ति है; लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भविष्य की वैश्विक कूटनीति कैसी होगी–क्या यह ऐसे ही धीरे-धीरे महिलाओं के लिए खुलती जाएगी या कोई नई संरचनात्मक क्रांति इसे और तेज़ी से बदल देगी, विशेषकर ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु संकट, तकनीकी असमानता, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और सामूहिक मानव सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रही है; इन सभी प्रश्नों के केंद्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका

है कि महिलाओं द्वारा संचालित वार्ताएँ समुदायों की जरूरतों के अनुरूप अधिक न्यायसंगत और अधिक टिकाऊ समाधान देती हैं, और इससे भी बढ़कर, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साझेदारी का रूप देती हैं; इसलिए जब हम "Women in Diplomacy" के ऐतिहासिक विकास को देखते हैं तो वास्तव में हम विश्व-राजनीति के विकास को देख रहे होते हैं–एक ऐसी राजनीति जो धीरे-धीरे शक्ति की कठोर व्याख्या से आगे बढ़कर न्याय, संवाद, समावेशन और भविष्य-उन्मुख सहयोग की दिशा में बदल रही है, और इस परिवर्तन का सबसे गहरा और सबसे स्थायी आधार महिला नेतृत्व ही है, जिसने कूटनीति को न केवल अधिक मानवीय बनाया बल्कि अधिक प्रभावशाली, अधिक विश्वसनीय और अधिक दीर्घकालिक भी, और इसी कारण भविष्य का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य किसी भी रूप में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्विक संतुलन, शांति और सहयोग की संरचना अब उस युग में प्रवेश कर चुकी है जहाँ महिला नेतृत्व केवल विकल्प नहीं, बल्कि वैश्विक आवश्यकता है।

निष्कर्ष

महिला नेतृत्व ने कूटनीति के इतिहास को केवल विस्तृत नहीं किया बल्कि उसे नया अर्थ, नई दिशा और नया मानवीय दृष्टिकोण दिया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे जटिल क्षेत्र में जहाँ पारंपरिक रूप से शक्ति, सामरिक क्षमता और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रमुख माना जाता रहा है, वहाँ महिलाओं ने संवाद, सहयोग, शांति-निर्माण, समुदाय-केन्द्रित समाधान और दीर्घकालिक स्थिरता को केंद्र में लाकर वैश्विक राजनीति की बुनियादी प्रकृति को बदला है; उन्होंने साबित किया है कि कूटनीति केवल शक्ति के प्रदर्शन का मंच नहीं बल्कि सहानुभूति, समझ, समावेशन और धैर्य का अभ्यास भी है, और जब निर्णय-निर्माण में विविधता शामिल होती है तो नीतियाँ अधिक प्रतिनिधि, अधिक संतुलित और अधिक प्रभावी होती हैं; आज भी यह यात्रा अधूरी है, बाधाएँ मौजूद हैं, संस्थागत असमानताएँ बनी हुई हैं, परंतु यह भी स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व अब वैश्विक कूटनीति का भविष्य निर्धारित कर रहा है–संयुक्त राष्ट्र की मेज से लेकर द्विपक्षीय वार्ताओं, शांति-संधियों, विकास साझेदारी और रणनीतिक निर्णयों तक, महिलाओं की उपस्थिति न केवल आवश्यक है बल्कि विश्व-व्यवस्था की स्थिरता और न्याय की अनिवार्य शर्त बन चुकी है, इसलिए "Women in Diplomacy" का ऐतिहासिक विकास केवल अतीत का वृत्तांत नहीं बल्कि भविष्य की दिशा है, और यही दिशा एक अधिक शांतिपूर्ण, अधिक न्यायसंगत और अधिक संवेदनशील वैश्विक व्यवस्था का आधार बनेगी।

संदर्भ

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद. महिला, शांति और सुरक्षा—संकल्प 1325. संयुक्त राष्ट्र अभिलेखागार; 2000.
2. यूएन वुमेन. कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक रिपोर्ट. यूएन वुमेन; 2019.
3. विश्व आर्थिक मंच. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020–2024. डब्ल्यूईएफ; 2024.
4. इंटरनेशनल पीस इंस्टिट्यूट. विमेन इन पीस नेगोशिएशंस: ए ग्लोबल मैपिंग. न्यूयॉर्क: आईपीआई; 2018.
5. हडसन V, वेलेंटाइन S, शेफर्ड L. द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2019.
6. टाउनसेन्ड A. वीमेन एंड डिप्लोमेसी इन द 20th सेंचुरी. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; 2017.
7. ब्लैक NJ. वीमेन, वॉर एंड पीस. हार्वर्ड केनेडी स्कूल; 2016.
8. नॉर्वे विदेश मंत्रालय. आधुनिक कूटनीति में महिलाओं की भूमिका. सरकारी दस्तावेज; 2020.
9. यूरोपीय संघ विदेश सेवा. फेडेरिका मोगेरिनी एंड ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस: आधिकारिक रिपोर्ट. ईयू; 2015.
10. संयुक्त राष्ट्र महासभा अभिलेख. विजयलक्ष्मी पंडित: प्रथम महिला महासभा अध्यक्ष. यूएनजीए; 1953.
11. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार. भारतीय विदेश सेवा में महिला अधिकारियों का योगदान—ऐतिहासिक दस्तावेज. नई दिल्ली: एमईए; 2018.
12. राव N. द फ्रैक्चर्ड हिमालय: इंडिया–चाइना रिलेशंस. नई दिल्ली: पेंगुइन; 2021.
13. केओहाने R, नाए J. पावर एंड इंटरडिपेन्डेन्स. पियरसन; 2012.
14. रवांडा विदेश मंत्रालय. रवांडा में जेंडर समानता एवं कूटनीति. सरकारी घोषणा; 2019.
15. कोलंबिया शांति समझौता आयोग. कोलंबिया शांति प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका. सरकारी रिपोर्ट; 2016.
16. हॉक्सवर्थ ME. ग्लोबल जेंडर पॉलिटिक्स. वाइली; 2020.
17. संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन विभाग. विमेन पीसकीपर्स: ट्रेंड्स एंड इम्पैक्ट. यूएनडीपीकेओ; 2022.
18. इटली विदेश मंत्रालय. मोगेरिनी की बहुपक्षीय रणनीति. सरकारी दस्तावेज; 2017.
19. स्लॉटर A. ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस; 2004.
20. हार्वर्ड बेलफर सेंटर. नेशनल सिक्योरिटी और कूटनीति में महिलाएँ. नीति-पत्र; 2021.
21. चिली संविधान आयोग. संवैधानिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी. सरकारी रिपोर्ट; 2021.
22. संयुक्त राष्ट्र जनसंचार विभाग. यूएन में महिला नेतृत्व—ऐतिहासिक विवरण. यूएनडीजीसी; 2020.
23. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन. क्यों महिलाओं की भागीदारी शांति की स्थायित्व बढ़ाती है. नीति विश्लेषण; 2019.
24. शुक्ला N. भारतीय कूटनीति का इतिहास. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट; 2015.
25. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार. इंदिरा गांधी: विदेश नीति और वैश्विक शांति—भाषण संग्रह 1972–1982. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग; 1982.
26. स्वराज S. डिजिटल डिप्लोमेसी एंड इंडिया's ग्लोबल कनेक्ट. एमईए अभिलेख; 2016.
27. नीति आयोग. महिला नेतृत्व और शासन क्षमता. नीति आयोग रिपोर्ट; 2020.
28. विश्व बैंक. विमेन एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. विश्व बैंक; 2023.
29. हार्वर्ड जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स. जेंडर एंड डिप्लोमेसी—विशेषांक. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी; 2018.
30. यूसीएलए स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़. हिस्टोरिकल मैपिंग ऑफ वुमेन डिप्लोमैट्स. यूसीएलए; 2022.

How to Cite This Article

यादव वीके. कूटनीति में महिलाएँ: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक विकास. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टिडिसिप्लिनरी एवोल्यूशनरी रिसर्च. 2025;6(2):137-140.

Creative Commons (CC) License

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work non-commercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.